जीवन में हमेशा एकदूसरे को समझने का प्रयत्न करिए, परखने का नहीं।
– अज्ञात

देश भर में उग्र विरोध

कई विश्वविद्यालयों के छात्रों को इस कानून ने बहुत बेचौन किया है। इसके विरोध में वे सड़क पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस क्रम में कई जगहों पर बसें जलाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी हुई हैं।

लक्ष्मी रानी

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को देश भर में उग्र विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर के राज्यों से हुई और धीरे–धीरे यह दिल्ली, मुंबई, अलीगढ़, लखनऊ, पटना और बेंगलुरु तक फैल गया। पूर्वोत्तर राज्यों में इसे लेकर लोगों में इस कदर गुस्सा है कि कर्फ्यू के बाद भी भीड़ सड़कों पर उतरी हुई है। उन राज्यों और साथ ही पश्चिम बंगाल के भी कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। कई विश्वविद्यालयों के छात्रों को इस कानून ने बहुत बेचौन किया है। इसके विरोध में वे सड़क पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस क्रम में कई जगहों पर बसें जलाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी हुई हैं।

दिल्ली में जामिया मिलिया के छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की है। वह जामिया परिसर में घुस आई और छात्रों को बेवजह पीटा। पिटाई से कई छात्र घायल हुए हैं। विश्वविद्यालय 5 जनवरी तक बंद कर दिया गया है और स्टूडेंट्स अपने घर जाने लगे हैं। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि कुछ शरारती तत्वों को खदेड़ते हुए वह परिसर में घुसने को मजबूर हुई। वहां छात्रों ने उस पर हमले किए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस आरोप–प्रत्यारोप के बीच राजधानी के आम लोग हकीकत को लेकर उलझन में हैं। एक तरह की अनिश्चितता और असुरक्षा पूरे देश में दिखाई पड़ रही है। यहां तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी कहना पड़ा है कि इस मामले में जुडिशरी तभी कुछ कर सकती है जब हिंसा, आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां खत्म हों।

समझने की जरूरत है कि नागरिकता कानून संसद से पारित हुआ है, जो देश की प्रतिनिधि संस्था है। इसके पीछे सरकार की अपनी सोच है, जिससे असहमत होने का अधिकार हर किसी को है। भारतीय लोकतंत्र में असहमति जताने के तरीकों की कोई कमी नहीं है। इस कानून को अदालत में चुनौती दी गई है, जिसने कई कानूनों को पहले भी रोका है और उनमें संशोधन कराया है। ऐसे में अगर कोई कहता है कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के जरिये ही किया जा सकता है तो उसकी बात पर कान नहीं देना चाहिए। पुलिस की तरफ से अगर पर्याप्त एहतियात बरता जाए, तब भी इस तरह के विरोध को हिंसक होते देर नहीं लगती।

इससे जान–माल का नुकसान तो होता ही है, रोजमर्रा का कामकाज भी पटरी से उतर जाता है, जिसका सबसे बड़ा घाटा सबसे कमजोर लोगों को उठाना पड़ता है। मुद्दा भटक जाता है, सो अलग। इस खास मामले में हिंसा की तस्वीरों का सांप्रदायिक उपयोग बहुत आसान है, लिहाजा अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए।

इस कानून से असहमत हर व्यक्ति यह जान ले कि अपनी चिंता में वह अकेला नहीं है। कई विपक्षी दलों ने भी खुलकर इस पर सवाल उठाए हैं। यह लोकतांत्रिक विमर्श का मुद्दा बने, इसके लिए पहली जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है कि वे लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करें।

भगवान क्या है?

श्री श्री रवि शंकर।

धर्म-दर्शन

भगवान सुन्दरता है। भगवान विस्तार, खुशी और प्रेम है एवं भगवान सर्वव्यापी है। भगवान वह विस्तार है जिसमें सब कुछ विद्यमान है, जिससे हर वस्तु अस्तित्व में आई है, और जिसमें हर वस्तु विलीन हो जाती है। तुम्हारे आस पास का विस्तार मृत नहीं हैय यह ऊर्जा एवं बुद्धिमत्ता से भरा है। वह ऊर्जा एवं बुद्धिमत्ता दिव्यता है। वह हर जगह है– आपके अन्दर एवं बाहर। एक बार जब एक शिष्य ने पूछा कि भगवान क्या है, तो गुरु ने सौम्यता से उत्तर दिया कि भगवान सत्य, सुन्दरता एवं प्रेम है। भगवान वह क्षेत्र एवं ऊर्जा है जो पूर्ण सृजन के हर कण में विद्यमान है। आप इसे महसूस कर सकते हैं परन्तु देख नहीं सकते। आप गहरे ध्यान में जाकर उस असीम शक्ति को अनुभव कर सकते हैं।

संपादकीय

कम पूंजी के सहारे

भारत में भूमंडलीकरण और उदारीकरण के बाद वित्तीय पूंजी के गजब रंग देखने को मिले हैं। कारोबार के बदले माहौल में कम पूंजी के सहारे भी देखते–देखते बड़ा कारोबार खड़ा कर लेना संभव हो गया है। यही वजह है कि नए भारतीय उद्ममी ऐसे दायरों से निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनसे पैसा कमाने के बारे में हाल तक कोई सोचता भी नहीं था। कुछ लोग बैंकों से कर्ज लेकर भी मालामाल हुए, लेकिन यह सफलता का कोई हिट फॉर्मूला नहीं है। कई नामी–गिरामी उद्यमी इसी में बर्बाद भी हो गए। इधर देश में दसियों नए अरबपति उभरे हैं तो कुछ पुराने अरबपतियों की लुटिया भी डूब गई है। हालांकि अरबपतियों के उभरने की रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा यहीं है। संपत्ति सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक की 'द वेल्थ रिपोर्ट 2019' के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2013 में यह 55 थी जो 2018 में बढ़कर 119 हो गई। फिलाडेल्फिया की टेंपल यूनिवर्सिटी के तहत फॉक्स स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रफेसर चार्ल्स धनराज के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में देश का कारोबारी माहौल लगातार सुधरा है। पूंजी की उपलब्धता और प्राइवेट इक्विटी में बढ़ोतरी से नए उद्यमों को बढ़ावा मिला है।

इधर उभर कई स्टार्ट अप्स आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की वित्तीय पूंजी के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। फ्लिपकार्ट इसका अच्छा नमूना है। बिन्नी बंसल और सचिन बंसल द्वारा शुरू की गई यह कंपनी एक दशक के भीतर ही भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन खुदरा विक्रेता बन गई। पिछले साल उन्होंने इसे वॉलमार्ट को बेच दिया और अरबपतियों की जमात में शामिल हो गए।

उनमें से ज्यादातर ने कहा कि सरकारी नौकरी हासिल करना उनका लक्ष्य है, जबकि प्राइवेट नौकरियों के बारे में उनकी राय नकारात्मक थी।

सरकारी नौकरी हासिल करना

रूचि जड़ौत

यह कैसा विरोधाभास है कि एक तरफ सरकारी नौकरियां सिमटती जा रही हैं, दूसरी तरफ युवाओं में इनका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। इसका मुख्य कारण है निजी क्षेत्र की नौकरियों से मोहभंग। उदारीकरण और नई आर्थिक नीति अपनाने के बाद एक दौर ऐसा आया था जब युवाओं ने प्राइवेट सेक्टर को तरजीह दी। सरकारी नौकरियां छोड़कर उन्होंने कॉरपोरेट हाउसेज जॉइन किए। लेकिन अभी यह ट्रेंड खत्म हो गया है।

सरकारी नौकरियां एक बार फिर पहले की ही तरह यूथ की प्राथमिकता बन गई हैं। सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज (सीईएस) का एक सर्वे इस बदलते ट्रेंड पर रोशनी डालता है। सीईएस ने दिल्ली, जयपुर और इलाहाबाद में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जुटे 515 विद्यार्थियों के विचार जाने, जिनमें 72 फीसदी ग्रेजुएट और 19 प्रतिशत पोस्ट ग्रेजुएट थे। उनमें से ज्यादातर ने कहा कि सरकारी नौकरी हासिल करना उनका लक्ष्य है, जबकि प्राइवेट नौकरियों के बारे में उनकी राय नकारात्मक थी।

उनका कहना था कि निजी क्षेत्र की नौकरियां एक तो सुरक्षित नहीं होतीं। उनमें शोषण होता है,

फिर ज्यादा घंटे काम के बदले में वेतन भी कम मिलता है। उनमें से कई छात्र पहले प्राइवेट नौकरी कर चुके थे। उनका कहना था कि निजी क्षेत्र से दिल टूट जाने के बाद वे सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयासरत हैं। उनमें से ज्यादातर की यह राय थी कि बेरोजगारी की समस्या तभी सुलझेगी जब सरकार सभी जरूरी पदों पर नियमित नियुक्ति करे। उन्होंने ध्यान दिलाया कि बहुत सारे पद खाली पड़े हैं लेकिन सरकार उन्हें भरने की कोशिश नहीं करती।

पिछले कुछ समय से जिस तरह सरकार के चतुर्थ वर्गीय पदों के लिए एमए, पीएचडी और एमबीए जैसे योग्यता रखने वालों ने आवेदन किए। उससे भी यह साबित होता है कि आज शिक्षित युवा वर्ग सरकारी नौकरी को कितना अहम मानता है। यह सही है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने और निजी सेक्टर को बढ़ावा मिलने से नई नौकरियां पैदा हुईं, लेकिन वे उन्हीं युवाओं को मिलीं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। आज भी ये कंपनियां अपने व्यापारिक मकसद से उन्हीं युवाओं को रख रही हैं जो किसी विशिष्ट तकनीकी क्षेत्र में निपुण हैं।

शुरू में इन्होंने आकर्षक वेतन भी दिए लेकिन अर्थव्यवस्था में आए ठहराव ने इन्हें अपने हाथ खींचने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने कम लोगों में काम चलाने की नीति अपनाई और ऊंची तनख्वाह देने में भी कंजूसी करने लगीं। इसके अलावा श्रम मानकों को लेकर कोई सख्ती न होने से इन कंपनियों ने न तो काम के घंटे निश्चत किए न ही प्रोन्नति वगैरह की कोई ठोस नीति बनाई। सरकार के लिए यह एक चेतावनी है। उसे अपनी नौकरियों का दायरा बढ़ाना होगा, साथ ही ऐसी नीति बनानी होगी कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के प्रति युवाओं के आकर्षण में कमी न आए।

अष्टयोग-4896

	1			2		3
5	33	3	35		27	
4		7	5	6	1	
	29		45		33	
	3		7		2	4
2	29	1	33	4	30	5
		5			6	1

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4895 का हल

7	4	5	2	3	6	1
5	38	3	32	1	27	7
4	3	7	5	6	1	2
3	29	2	45	7	33	6
1	3	6	7	5	2	4
2	24	1	36	4	30	5
6	1	4	7	2	5	3

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

गन्ना किसानों के जीवन में फिर घुली कड़वाहट

चौधरी पुष्पेन्द्र सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार दूसरे साल भी गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई, जिससे किसानों में भारी नाराजगी है। उन्होंने पिछले दिनों पूरे राज्य में जगह–जगह प्रदर्शन किया। 2017 में उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद अब तक के तीन चीनी वर्षों में मात्र 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जो नाकाफी है। इस साल गन्ना किसानों को गन्ने का भाव बढ़ने की उम्मीद थी। लगता है, योगी सरकार ने चीनी–उद्योग लॉबी के दबाव में दाम नहीं बढ़ाया, जबकि चीनी उद्योग की स्थिति देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस साल बिल्कुल बदल गई है। गौरतलब है कि इस वर्ष देश में कम चीनी उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग के कारण चीनी उद्योग को तो पूरी राहत मिलेगी, लेकिन गन्ना किसानों की स्थिति और बिगड़ेगी। 2018–19 में देश में चीनी का आरंभिक भंडार (ओपनिंग स्टॉक) 104 लाख टन, उत्पादन 332 लाख टन, घरेलू खपत 255 लाख टन और निर्यात 38 लाख टन रहा। वर्तमान चीनी वर्ष 2019–20 में चीनी का प्रारंभिक भंडार 143 लाख टन है।